VISION IAS
M N 25 AUG 2022 No. 3
RECEIVED

VISION IAS

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1835)

Name of Candidate	SUSHMA SAGAR		
Medium Eng./Hindi	HINDI	Registration Number	1370539
Center	ND	Date	25/8/2022

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar
Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. The withdrawal of general consent to the CBI by certain state governments in India threatens the spirit of cooperative federalism in India. Discuss.

(150 words) 10

भारत में कुछ राज्य सरकारों द्वारा सी. बी. आई. से सामान्य सहमति वापस लेना भारत में सहकारी संघवाद की भावना के लिए खतरा उत्पन्न करता है। चर्चा कीजिए।

हाल ही में प. बंगाल, केरल जैसे 9 राज्यों ने CBI से सामान्य सहमति को वापिस ले लिया।

CBI भारत की प्रमुख जाँच एजेंसी है जो भ्रष्टाचार के कानूनों के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर के अपराधों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इसी भूमिका के बेहतर सम्पादन के लिए राज्यों द्वारा सामान्य सहमति दी जाती है जिसके तहत जाँच के लिए बार-बार राज्यों से अनुमति लेने की अनिवार्यता नहीं रहती।

CBI से सामान्य सहमति से वापसी से सहकारी संघवाद को खतरा -

① CBI एक राष्ट्रीय एजेंसी है किंतु सामान्य सहमति का वापिस लिया जाना केंद्र-राज्यों के मध्य विश्वास घाटे की स्थिति को दर्शाता है।

- इससे दोनों के संबंध नकारात्मक रूप से प्रभावित होते है व राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर जाँच मे कमी आती है इससे संघवाद को नुकसान पहुँचता है।
- राज्यों का कहना है कि CBI का दुरूपयोग अपने राजनैतिक हितों की पूर्ति हेतु किया जाता है। इससे भी संघवाद कमजोर होता है।
- 2013 मे SC ने भी CBI को पिंजरे का तोता कहा था तथा आवश्यक सुधारों का निर्देश दिया था जिनका अभी तक पालन नही किया गया है।

इस प्रकार समग्रत: सहकारी संघवाद कमजोर हुआ है इसके लिए आवश्यक है - CBI निदेशक को स्वायत्ता देना, उनके पद को कैबिनेट सचिव के समान शक्तियाँ व रैंक प्रदान किया जाना, राजनीतिक इस्तेमाल का साधन न बनने देना, SC द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना आदि।

राष्ट्रहित के लिए सामान्य सहमति आवश्यक है अत: केंद्र व राज्य को सहयोग के माध्यम से इस एजेंसी के कार्यों की बाधाओं को दूर करना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. Stating the sources of finance for local self-governments in India, suggest ways to strengthen their financial position. **(150 words) 10**

भारत में स्थानीय स्व-शासी सरकारों के लिए वित्त के स्रोतों का उल्लेख करते हुए, उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के उपाय सुझाइए।

स्थानीय स्वशासन को मजबूती देने के लिए 73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासी सरकारों (LSGs) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

किंतु LSGs अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाने में सफल नहीं रही हैं इसका प्रमुख कारण है - निम्न वित्तीय स्थिति।

भारत में LSGs अपने साधनों से मात्र 6% वित्त ही जुटा पाती हैं जबकि ब्राजील जैसे देशों में यह 40% है। अतः अपने वित्त के लिए ये मुख्यतः

- राज्यों के अनुदान
- केंद्र सरकार से अनुदान
- राज्यों द्वारा वित्तीय हस्तांतरण
- स्थानीय करारोपण ex- सड़क, मेले हाउस टैक्स आदि।

से ही वित्त जुटाती हैं।

इनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए निम्न उपाय किए जाने चाहिए -

उपाय –

- कर एकत्रण की प्रक्रिया मे क्षमता निर्माण
  - पर्याप्त मानवीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएं
  - बेहतर प्रशिक्षण
- कार्यप्रणाली मे सुधार
  - दक्षता, कुशलता को बढ़ावा
  - संसाधनों का बेहतर क्रियांवयन
  - भ्रष्टाचार रोका जा सकेगा।
- बजट निर्माण की प्रक्रिया पर निगरानी रखना
  - ताकि विलम्ब न हो
  - रिसाव न हो।
- अनु 280 मे सुधार
  - राज्य वित्त आयोग को पर्याप्त शक्तियाँ दी जाए
  - इनके घाटे को राजकोषीय घाटे मे शामिल किया जाए।

बेहतर LSGs के माध्यम से भारत वास्तविक अर्थों मे अमृतकाल मे प्रवेश कर सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Cabinet Committees play an important role in reinstating collective responsibility and principle of homogeneity of the Executive in the Indian Parliamentary system. Elucidate. **(150 words) 10**

भारतीय संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडलीय समितियां सामूहिक उत्तरदायित्व और कार्यपालिका की एकरूपता के सिद्धांत को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्पष्ट कीजिए।

मंत्रिमंडलीय समितियाँ संविधानेतर निकाय है। इनका संबंध संसद की कार्य प्रणाली की नियमावली से होता है।

मंत्रिमंडलीय समितियों द्वारा सामूहिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना

- इनके निर्णयों को सरकार के निर्णय माना जाता है।
- इनके लक्ष्य व कार्यप्रणाली कार्यपालिका के लक्ष्यों को प्रतिबिम्बित करते है।
- बेहतर सुझावों का आगमन संभव
- कानूनों के प्रति बेहतर समझ रखते है जिससे संसद के प्रति बेहतर जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है
- मंत्रियों के ऊपर अतिरिक्त बोझ को कम करते है - संसदीय कार्यों में कुशलता आती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

मंत्रिमंडलीय समितियाँ व कार्यपालिका की एकरूपता के सिद्धांत की बहाली

- विभिन्न मंत्रालयों व विभागों के मध्य समन्वय का कार्य eg- आर्थिक मामलों की समिति, आर्थिक मामलों के संबंध में समन्वय व एकरूपता प्रदान करने में भूमिका निभाती है
- प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग के माध्यम से स्थायी व अस्थायी कार्यपालिका के मध्य एकरूपता।
- किसी भी संकट के समय बेहतर निर्णय लेना सक्षम होता है।

इस प्रकार संसदीय ढाँचे को मजबूत करने में मंत्रिमण्डलीय समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. There is a need to overhaul the public procurement and project management (PPPM) framework of India for faster, efficient and transparent execution of government projects. Comment.

(150 words) 10

सरकारी परियोजनाओं के तीव्र, कुशल और पारदर्शी निष्पादन के लिए भारत के सार्वजनिक खरीद और परियोजना प्रबंधन (PPPM) ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए।

सार्वजनिक खरीद और परियोजना (PPPM) प्रबंधन से तात्पर्य सार्वजनिक संस्थाओं व एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले क्रय-विक्रय की प्रक्रिया के बेहतर, कुशल व प्रभावी प्रबंधन से है।

PPPM ढाँचे में वर्तमान में कमियाँ

① निम्न लागत के सिद्धांत का पालन न होना
- इससे खरीद अधिक मूल्यों पर होती है।
- सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ता है।

② रिसाव व भ्रष्टाचार
- निम्न गुणवत्ता युक्त वस्तुओं की खरीद
- संसाधनों का अनुकूलतम दोहन नहीं हो पाता।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- निर्णय प्रक्रिया मे देरी
  - लाल फीताशाही
  - कागजी कार्यवाही पर अधिक बल
- पुराने बकाया का भुगतान न किया जाना
  - यह दक्षता को प्रभावित करता है।
- अवसंरचनात्मक सुधार की आवश्यकता
  - डिजीटलीकरण को बढ़ावा
  - e-GeM (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस)
  - दूर दराज तक आपूर्ति न होना।

सुधार
- व्यापक व समग्र फ्रेमवर्क व रणनीति व मानक बनाए जाने चाहिए।
- प्रक्रिया में समयबद्धता व लक्ष्यों को स्पष्ट ध्यान देने की आवश्यकता
- डिजीटलीकरण को बढ़ावा
- प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा जिससे न्यूनतम लागत प्राप्त की जा सके।
- पर्याप्त निगरानी फ्रेमवर्क
- दक्षता, कुशलता, जवाबदेहिता की आवश्यकता।

बेहतर PPPM सरकारी संस्थाओं की दक्षता वृद्धि हेतु आवश्यक कदम है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. Adequate measures are required to overcome the challenges and vulnerabilities associated with undertaking social accountability initiatives and institutionalising them. Elaborate. **(150 words) 10**

सामाजिक जवाबदेही पहलों को शुरू करने और उन्हें संस्थागत बनाने से जुड़ी चुनौतियों और कमजोरियों को दूर करने के लिए पर्याप्त उपायों की आवश्यकता है। सविस्तार वर्णन कीजिए।

सामाजिक जवाबदेही का अर्थ है समाज के नागरिक या उनके समूहों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जवाबदेहिता को सुनिश्चित किया जाना।

सामाजिक जवाबदेही से संबंधित वर्तमान में उपस्थित चुनौतियाँ व कमजोरियाँ

① सरकारी संस्थाओं द्वारा सहयोग न किया जाना
↳ इससे बेहतर मूल्यांकन नहीं हो पाता।

② सामाजिक जागरूकता की कमी
↳ गरीबी व अशिक्षा के कारण

③ पारदर्शिता का अभाव
↳ ऑफिशियल सिक्रेट एक्ट आदि के माध्यम से आवश्यक सूचनाएँ भी छुपा ली जाती हैं।

◎ <u>लाभार्थी वर्ग के हितों पर प्रभाव</u>

↳ उच्च मजबूत वर्ग, प्रशासनिक तंत्र अपने स्वार्थों के कारण इसे प्रोत्साहित नहीं होने देते।

◎ <u>सरकारी प्रक्रियाओं में जटिलताएँ</u>

↳ कागजों पर अधिक बल

↳ साधारण जन की भाषा का प्रयोग न होना

आवश्यक उपाय

- → सिविल सेवा प्रक्रिया में सुधार
- RTI (सूचना के अधिकार) को मजबूत बनाना
- ई-गवर्नेंस पर बल देना ↓ भ्रष्टाचार पर रोक
- नागरिक समाज NGOs की भूमिका बढ़ाना eg- MKSS मजदूर किसान सेवक संघ ने RTI के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
- सोशल ऑडिट को बढ़ावा eg- मनरेगा
- नागरिक चार्टर में सुधार

सामाजिक जवाबदेही लोकतंत्र के ढाँचे को मजबूत बनाती है।

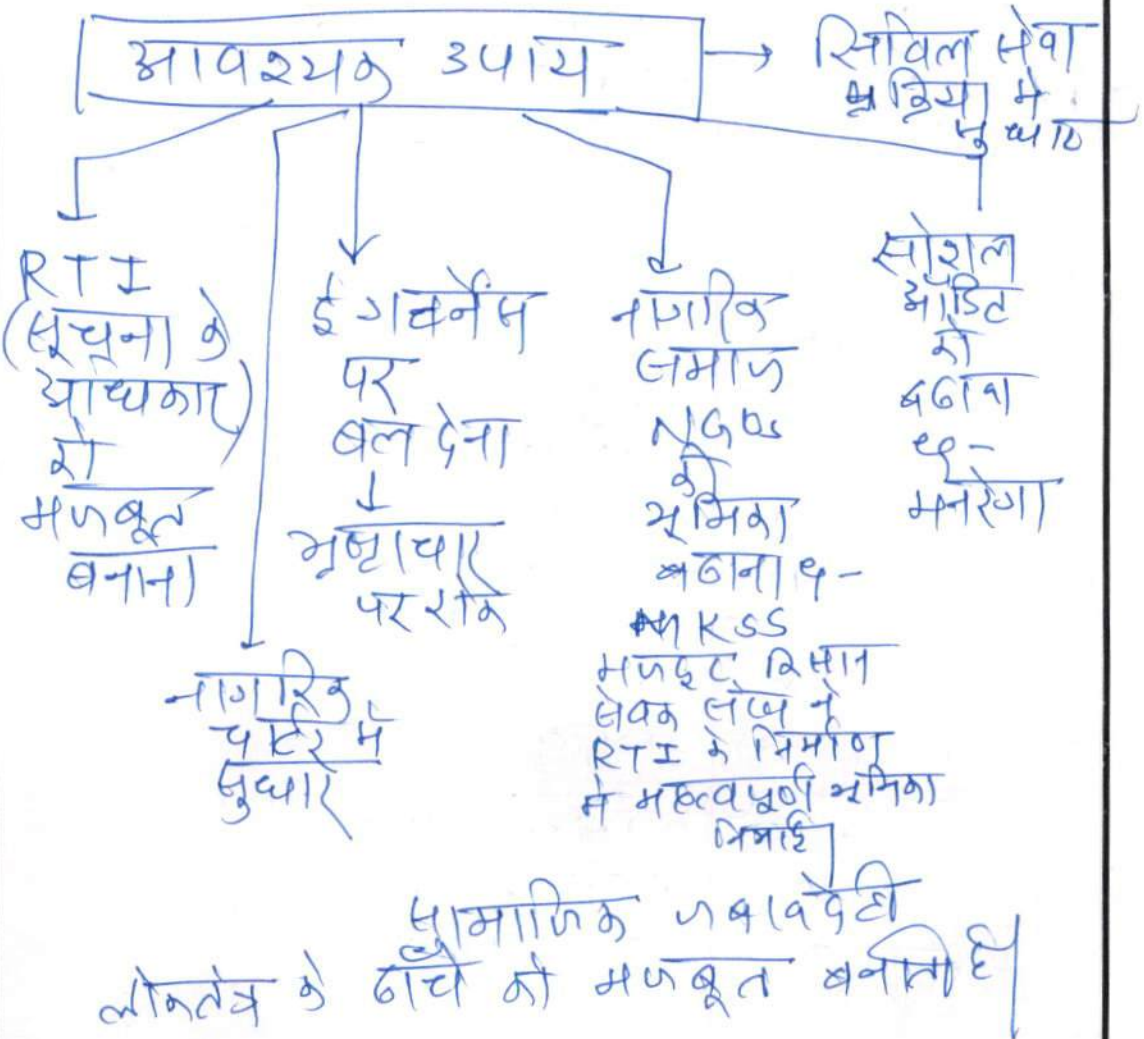

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. In view of the recent Parliamentary Standing Committee report, discuss the issues faced by the National Commission for Scheduled Tribes (NCST) and suggest measures that can be adopted to strengthen it. **(150 words) 10**

एक संसदीय स्थायी समिति की हालिया रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों की विवेचना कीजिए और इसे मजबूत बनाने के लिए अपनाए जा सकने वाले उपायों का सुझाव दीजिए।

संसदीय स्थायी समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि NCST (राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग) पिछले 4 वर्षों से निष्क्रिय पड़ा है व एक भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

NCST द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दे

- वित्त स्त्रोतों की कमी
  ↳ दक्षता व कुशलता प्रभावित
- मानव संसाधन की कमी
  ↳ भर्ती के कठोर मानक होने के कारण
- रिपोर्ट को मंत्रालयों द्वारा गंभीरतापूर्वक क्रियान्वयन न किया जाना
  ↳ आयोग को हतोत्साहित करता है।

- नियमित मीटिंग्स का अभाव
  - ↳ जनजातीय हित सुनिश्चित नहीं हो पाते।
- जवाबदेहिता की कमी
  - ↳ इससे निष्क्रियता को बढ़ावा मिलता है।

मजबूत करने के लिए उपाय —

- पर्याप्त वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की जाए
  - ↳ बेहतर क्रियान्वयन संभव
- पर्याप्त मानव संसाधन व प्रशिक्षण देना
  - ↳ भर्ती के मानकों को सरल करना
- जवाबदेहिता सुनिश्चित करना
  - ↳ कार्यप्रणाली में दण्ड व प्रोत्साहन की रणनीति को शामिल करना।
- नियमित मीटिंग्स की जाना।
- पर्याप्त शक्तियाँ हस्तांतरित की जाए
  - ↳ इससे रिपोर्ट का क्रियान्वयन भी किया जा सके।

जनजातीय हितों की रक्षा के लिए NCST में पर्याप्त सुधार वर्तमान समय की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. While the Mid-Day Meal scheme was aimed at fulfilling the nutritional needs of students, it is far behind in achieving this objective. Discuss. Also, suggest remedial measures in this context. **(150 words) 10**

यद्यपि मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य छात्रों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना था, किंतु इस उद्देश्य को प्राप्त करने में यह काफी पीछे है। चर्चा कीजिए। साथ ही, इस संदर्भ में उपचारात्मक उपायों का सुझाव दीजिए।

मध्याह्न भोजन योजना (MDM) । विश्व का सबसे बड़ा स्कूल फीडिंग प्रोग्राम है। इसका प्रमुख उद्देश्य था - छात्रों में पोषण सुनिश्चित करना, नामांकन दर में सुधार करना आदि।

MDM पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी पीछे है

① गुणवत्ता पूर्ण भोजन का अभाव
↳ इसके कारण बच्चों की मृत्यु व बीमार होने जैसी घटनाएँ सामने आती रहती है।

② पोषण का अभाव
↳ सभी पोषण युक्त तत्वों को थाली में शामिल नहीं किया जाता है। इससे कुपोषण की समस्या के कारण स्टंटिंग, वेस्टिंग, अण्डर ग्रोथ देखी जा सकती है

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

① भेदभाव

- कई स्कूलों में निम्न वर्ग के जातियों के साथ भेदभाव पूर्ण स्थिति की घटनाएँ सामने आई है।

② भ्रष्टाचार व रिसाव

- इससे भी यह योजना सफल नहीं हो सकी है।

उपचारात्मक उपाय :-

① थाली को विविधता प्रदान करना

- इसमें दाल, सोयाबीन, अण्डा, दूध, मोटा अनाज आदि को शामिल किया जाना चाहिए।

② स्कूलों में विभिन्न फलों व सब्जियों को उगाया जाना

- क्षेत्रीय शिक्षा नीति का प्रावधान

③ पूरी प्रक्रिया का अधिकतम डिजीटलीकरण व निगरानी रखना

- इससे भ्रष्टाचार न हो।

④ जवाबदेहिता सुनिश्चित करना

- बेहतर क्रियान्वयन संभव होगा।

MDM देश में पोषण व शिक्षा व्यवस्था में पर्याप्त सुधार लाने की क्षमता रखती है अतः इसकी कमियों को दूर किया जाना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. Sexual and reproductive health and rights (SRHR) remain critical for the attainment of the Sustainable Development Goals (SDGs). In this context, discuss the impediments in the fulfilment of SRHR in India. Also, mention the steps that can be taken in this regard. **(150 words) 10**

सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति के लिए यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार (SRHR) महत्वपूर्ण हैं। इस संदर्भ में, भारत में SRHR की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इस संबंध में उठाए जा सकने वाले कदमों का भी उल्लेख कीजिए।

यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार (SRHR) से तात्पर्य बेहतर यौन व प्रजनन स्वास्थ्य सुविधाओं तक वहनीय पहुंच को सुनिश्चित करना।

इसके माध्यम से SDG-3 (बेहतर स्वास्थ्य स्थापित करना SDG-5 लैंगिक समानता स्थापित करना को पूर्ण किया जा सकता है।

भारत में SRHR में आने वाली बाधाएं

@ संकुचित दृष्टिकोण

↳ परिवार व समाज में इसकी चर्चा को अभी भी वर्जना की दृष्टि से देखा जाता है।

↳ बाल विवाह की घटनाएँ

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

⑥ अवसंरचना व सुविधाओं की कमी
↳ वहनीयता की समस्या
↳ सभी तक पहुँच का अभाव
⑦ जागरूकता का अभाव
⑧ पर्याप्त शिक्षा का अभाव
↳ स्कूल में भी पाठ्यक्रम में इसे विस्तृत तरीके से समझाया नहीं जाता जिसका प्रभाव किशोर-किशोरियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है।
⑨ शुद्धता की अवधारणा
↳ अभी भी मासिक धर्म आदि को अशुद्ध माना जाता है अतः पर्याप्त देखभाल नहीं हो पाती
eg- सबरीमाला का मुद्दा

उपाय → बाल विवाह पर रोक

- पर्याप्त जागरूकता फैलाई जाए
- NGOs व नागरिक समाज की भूमिका बढ़ाई जाए
- इनके आधानों में लैंगिक समानता अपनाई जाए eg- नसबन्दी
- सस्ती तक निशुल्क व वहनीय पहुँच सुनिश्चित हो

बेहतर प्रजनन व यौन स्वास्थ्य देश में बेहतर मानवीय संसाधनों के निर्माण पर देश के SDGs लक्ष्यों की प्राप्ति में भूमिका निभा सकता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. State the functions of the United Nations Human Rights Council. Also, discuss the issues faced by the Council in the promotion and protection of human rights around the globe. **(150 words) 10**

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के कार्यों का उल्लेख कीजिए। साथ ही, विश्व भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनके संरक्षण में परिषद द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों की विवेचना कीजिए।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC), UN की एक अंतरसरकारी संस्था है जिसमें 47 सदस्य देश शामिल है।

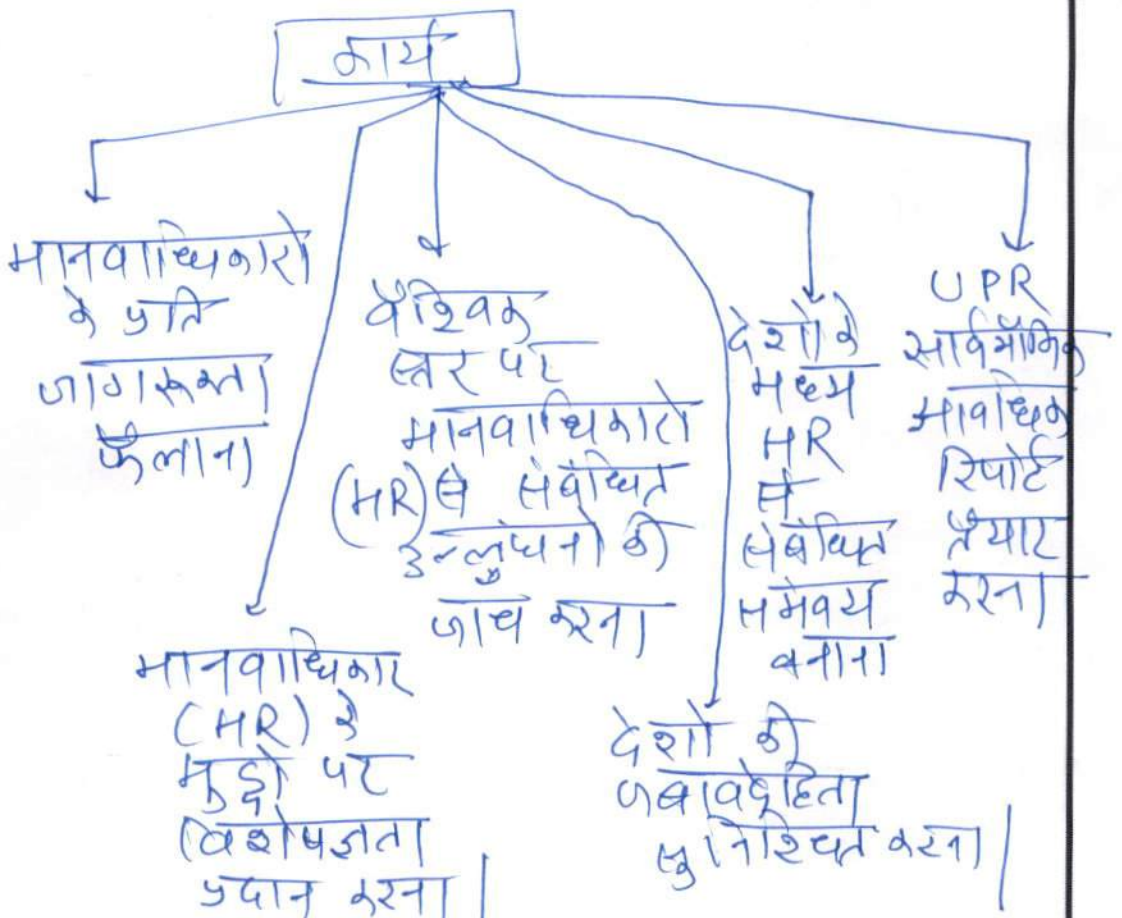

UNHRC द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दे इस प्रकार है -

(b) स्पष्ट परिभाषा का अभाव
↳ इसके कारण मानवाधिकारों की उचित सुरक्षा नहीं हो पाती।

(c) राष्ट्रों के निजी हित
↳ इनकी पूर्ति के लिए वे मानवाधिकारों के उल्लंघन को भी अधिक महत्व नहीं देते।

(d) मानवाधिकारों के उल्लंघन वाले देशों का सदस्य देश के रूप में होना
↳ हितों का संघर्ष

(e) समर्थक नागरिक समाज के प्रति प्रतिशोध की भावनाएँ
↳ राष्ट्रों द्वारा उनका शोषण किया जाता है।

उपाय

- चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता, खुले मतदान को बढ़ावा
- UPR का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- सदस्यता समाप्त करने के मानक सरल बनाना।
- पर्याप्त शक्तियाँ दीए।

इस प्रकार मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए UNHRC में पर्याप्त सुधारों की आवश्यकता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. West Asia is an important strategic region for India with profound geo-political and geo-economic significance. Discuss. **(150 words) 10**

अत्यधिक भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक महत्व के कारण पश्चिम एशिया भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र है। चर्चा कीजिए।

भारत की वर्तमान समय की आवश्यकताओं व पश्चिम एशिया में तेजी से बदलती परिस्थितियाँ भारत-प.एशिया के मजबूत संबंधों को अनिवार्य बनाती है।

अत्यधिक भू-राजनीतिक महत्व के कारण प.एशिया का भारत के लिए महत्व

① कनेक्टिविटी
↳ INSTC (अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा), चाबहार पोर्ट आदि के दृष्टि से प.एशिया अत्यंत महत्वपूर्ण है।

② चीन को प्रतिसंतुलित करना
↳ इस क्षेत्र में चीनी गतिविधियों में वृद्धि होना

③ इन देशों का पश्चिमी देशों के अलावा अन्य देशों से संबंधों के सुधार पर बल देना
↳ भारत के लिए अवसर अपनी

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

करता है
↳ सऊदी अरब का 2030 का विजन

⑥ सामरिक महत्व
↳ 370 के हटाने पर सऊदी अरब व UAE द्वारा भारत का समर्थन
↳ भारत को OIC में आमंत्रित करना आदि।

⑦ I2U2 समूह
- इसमें भारत, इजराइल, UAE, USA शामिल है।
- बेहतर सम्बंध

⑧ बड़ी संख्या में प्रवासियों की सेवा निवास करती है

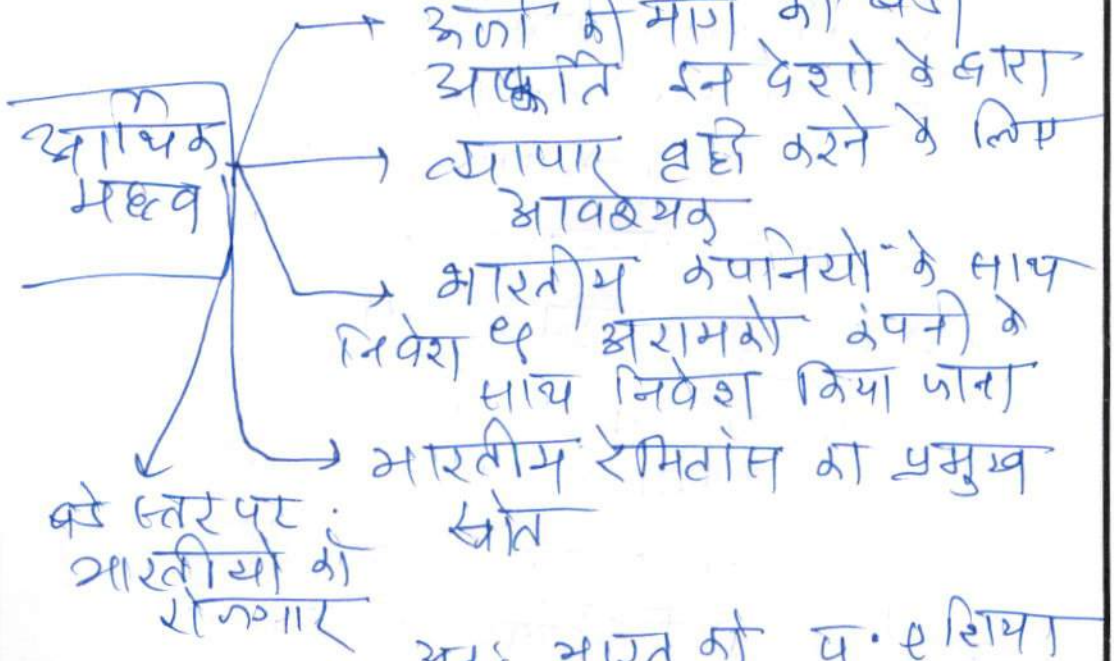

अतः भारत को प० एशिया के साथ संबंधों को और अधिक बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. Disenfranchising prisoners desecrates a cherished value in a democracy i.e. 'right to vote', which should be guarded earnestly. Discuss in the light of The Representation of The People Act, 1951. **(250 words) 15**

कैदियों को मताधिकार से वंचित करना वस्तुतः लोकतंत्र के एक प्रशंसनीय मूल्य, अर्थात् "मतदान के अधिकार" का अपमान करना है, जिसकी गंभीरतापूर्वक रक्षा की जानी चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के आलोक में चर्चा कीजिए।

भारत में सार्वभौमिक मताधिकार की संकल्पना को अपनाया गया है अर्थात् सभी की भागीदारिता से राजनीतिक न्याय को स्थापित किया गया है।

लोक प्रतिनिधित्व अधि॰ 1951 की धारा 62 के अनुसार - किसी व्यक्ति को मतदान के अधिकार से वंचित रखा जा सकता है जब वह जेल मे हो (दोषसिद्ध कैदी हो या विचाराधीन कैदी) या पुलिस की कानूनी हिरासत मे हो।

इस दृष्टि से जेल मे बंद लोगो को मतदान के वंचित रखने के पक्ष मे निम्न

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

तर्क दिए जाते हैं -

① चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता
↳ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की भागीदारिता से शुद्धता कमजोर पड़ती है

② अपराधियों द्वारा अपराध से सामाजिक अनुबंध तोड़ा जाता है
↳ अतः उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जा सकता है।

③ नैतिक मानदण्ड
↳ इससे लोगों में बेंचन की भावना आती है जिससे वे अपराध से बचने का प्रयास करते हैं। यह नैतिक दबाव का कार्य करता है।

④ संसाधनों की आवश्यकता
↳ बड़े मात्रा में परिवहन व सुरक्षा संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी।

⑤ सिविल डेथ
↳ जेल में बंद लोगों के अन्य अधिकार भी निलम्बित हो जाते हैं

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

विपक्ष में तर्क -

① अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के विरुद्ध
↳ केवल दोषसिद्ध अपराधियों को प्रतिभाग करने से बाहर रखा जाता है।

② दोहरा दंड
↳ अपराध का दंड व राजनीतिक अधिकार का भी बहिष्कार

③ भेदभाव जेल में
↳ विचाराधीन व्यक्ति के चुनाव लड़ने से मनाही नहीं की गई है जबकि वह मतदान नहीं दे सकता है।

④ सिविल डेथ की अवधारणा पुरानी हो चुकी है
↳ न्यायालय कई बार कह चुका है कि कैदियों के भी स्वतंत्र नागरिकों के समान अधिकार होते हैं।

अतः आवश्यकता है कि पहले विचाराधीन कैदियों को मतदान का अधिकार व फिर चरणबद्ध तरीके से सभी को मतदान अधिकार देने हेतु परिस्थितियों का निर्माण किया जाए।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. There are similarities and interactions between the affirmative action adopted by India and USA owing to similar historical injustices faced by their respective vulnerable groups. Discuss. **(250 words) 15**

भारत और यू. एस. ए. के सुभेद्य समूहों द्वारा सामना किए गए एकसमान ऐतिहासिक अन्याय के कारण, इनके द्वारा अपनाई गई सकारात्मक कार्रवाई के बीच समानताएं हैं और इनका एक-दूसरे पर प्रभाव पड़ा है। चर्चा कीजिए।

भारत व USA विश्व के दो प्रमुख व शक्तिशाली लोकतंत्र है। भारत जहाँ विश्व का वृहतम लोकतंत्र है वहीं USA विश्व का पहला लोकतंत्र है। लोकतंत्र व सामाजिक संरचना ने दोनो के मध्य समानता स्थापित की है।

भारत व USA में सुभेद्य समूहो द्वारा सामना किए गए ऐतिहासिक अन्याय

---

① USA में रंगभेद की नीति के तहत सामाजिक पद सोपान दिखता है

② भारत में जाति व्यवस्था के तहत सामाजिक पद सोपान दिखता है।

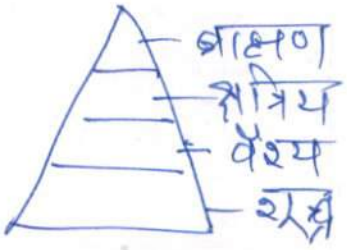

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

* इसके साथ ही दोनों देशों में महिलाओं, अल्पसं LGBTQ समुदाय जैसे सुभेद्य समूह है जिनके लिए न्याय की माँग अभी भी जारी है।

दोनों देशों द्वारा अपनाई गई सकारात्मक कार्रवाई के बीच समानताएँ

* दोनों देशों ने लोकतंत्र को मजबूती प्रदान कर संरक्षण दिया है।
* मौलिक अधिकारों की विस्तृत अवधारणा व गारंटी देना
* USA में कोटा व्यवस्था है किंतु भारत की आरक्षण व्यवस्था अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट है।
* न्यायपालिका में स्वतंत्रता

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- संवैधानिक संस्थाओं को पर्याप्त शक्तियाँ।
- NGOs, नागरिक समाज की महत्वपूर्ण भूमिका।
- शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र आदि में पर्याप्त निवेश।
- विकास आधारित योजनाएँ संचालित करना।

इन प्रयासों के बावजूद भी पूरी तरह से सामाजिक अन्याय को दूर नहीं किया जा सकता है

↳ USA में रंगभेद आधारित हिंसाएँ जारी

↳ भारत में जाति आधारित हिंसाएँ जारी - 14 Aug 2022 को जालौर में 9 साल के दलित बच्चे की मृत्यु की घटना

दोनों देश अपनी सकारात्मक कार्यवाई के तहत सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. Objections to domicile-based reservation in private sector jobs on the grounds of constitutional equality and freedom are misplaced. Critically discuss. **(250 words) 15**

संवैधानिक समानता और स्वतंत्रता के आधार पर निजी क्षेत्रक की नौकरियों में अधिवास आधारित आरक्षण पर आपत्ति अनुचित है। समालोचनात्मक चर्चा कीजिए।

हाल ही में हरियाणा में निजी क्षेत्रक में 30 हजार से कम आय वाले नौकरियों में 75% स्थानीय आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

संवैधानिक समानता व स्वतंत्रता के आधार पर अधिवास आधारित आरक्षण के पक्ष में तर्क

① भारत में अनु० 14 के तहत विधि की समता के साथ विधियों का समान संरक्षण की अवधारणा को स्वीकार गया है अतः देश की विकास योजना हेतु भिन्न वर्ग हेतु असमान व्यवहार किया जा सकता है।

② संविधान द्वारा निजी क्षेत्र में आरक्षण पर रोक नहीं

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

लगाई गई है।

- अनु 19
  5 के तहत प्राप्त कोई भी आजीविका अपनाने का अधिकार निगमों को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देता। राज्य द्वारा इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है

- इससे बाहरी व आंतरिक के मध्य के संघर्ष को समाप्त कर शांति स्थापित की जा सकती है eg- असम में नृजातीय संघर्ष।

अधिवास आधारित आरक्षण के विपक्ष में तर्क -

- देश की एकता व अखण्डता को बनाए रखना संविधान का आधारभूत ढांचा है (1973 केशवानंद भारती वाद)
- यह आरक्षण देश की एकता को खतरा पहुंचा सकता है।

आज राज्य के आधार पर तो भविष्य में जिला के स्तर पर स्थानीय आरक्षण की मांग की जा सकती है।

- उपराष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा मिलेगा।
- सेक्टवाद को बढ़ावा मिलेगा।
- भूमिपुत्र की संकल्पना।
- राज्य के मजबूत स्थिति व स्थायित्व के लिए निवेश आवश्यक है किंतु MNCs आदि पर ऐसी शर्तें निवेश को कम कर सकती है।
- श्रम के समन्वय पर रोक लगेगी साथ ही अबाध्य विचरण पर भी रोक लगेगी।

यह देश की स्थिति, स्थायित्व व मूल्यों को कमजोर कर सकता है जो संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है।

इस प्रकार राज्यों को चाहिए कि वोट बैंक की राजनीति के स्थान पर रोजगार के अवसर सृजित किए जाए। इससे लोगों में आरक्षण की मांग व संघर्ष भी कम हो जाएगी।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. There have been arguments that sedition law is an attack on the very foundation of India's liberal democratic principles, as enshrined in the Constitution. Do you agree? **(250 words) 15**

ऐसा तर्क दिया जाता है कि राजद्रोह कानून भारत के उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतों की नींव पर हमला है, जैसा कि संविधान में निहित हैं। क्या आप सहमत हैं?

IPC की धारा 124A में राजद्रोह का प्रावधान किया गया है जिसके तहत मौखिक या लिखित या सांकेतिक किसी भी रूप में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा, हिंसा, अवमानना को बढ़ावा देना राजद्रोह है।

यह गैर जमानती अपराध है व इससे उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। गाँधी से लेकर तिलक, अरुंधती रॉय आदि पर इसके आधार पर मुकदमे दायर किए गए थे।

राजद्रोह, लोकतांत्रिक सिद्धांतों की नींव पर हमला

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आलोचना को सीमित करना

↳ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार की आलोचना आवश्यक है किंतु इसे ये कानून सीमित करता है।

विपक्षी विचारधारा के प्रतिशोध का माध्यम

↳ इसका दुरुपयोग अपने निजी हित के लिए किया जाता है।

संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध

↳ अनु. 19 के तहत प्राप्त वाक् व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाता है।

दुरुपयोग

↳ अंग्रेजों ने इसका प्रयोग अपने हित में किया।
↳ स्पष्टता के अभाव में
↳ राज्यों द्वारा मनमाने पूर्ण परिभाषा दिया जाना।
↳ प्रावधानों में अतिव्यापन

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

राजद्रोह के पक्ष में तर्क

① कई आतंकवादी, विद्रोही शक्तियों द्वारा विधि द्वारा स्थापित सरकार को उखाड़ने हेतु वाक् व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया जाता है।

② राजनीतिक स्थायित्व - असमाजिक तत्वों पर कार्यवाही से सामाजिक समरसता बनी रहती है।

③ देश की एकता, अखण्डता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

④ 1962 के केदारनाथ वाद में उच्चतम न्यायालय ने भी राजद्रोह को निरंतर रखने हेतु स्पष्टता लाने का आदेश दिया था।

अतः राजद्रोह को निरंतर रखा जाना चाहिए किंतु यह सुनिश्चित रहे कि इसका उपयोग राजनीतिक ध्रुवीकरण के साधन के रूप में न हो।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. Despite Government e-Marketplace facing certain challenges, it has brought about a significant improvement in the procurement of goods and services by various government agencies. Discuss. **(250 words) 15**

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस द्वारा कुछ चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, इन्होंने विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में महत्वपूर्ण सुधार किया है। चर्चा कीजिए।

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के माध्यम से सरकारी संस्थाओं व एजेंसियों के द्वारा वस्तुओं व सेवाओं की खरीद की जाती है

GeM में व्याप्त चुनौतियाँ -

① **क्षमता का पूर्ण दोहन नहीं**
↳ सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कम का ही क्रय-विक्रय किया जा रहा है।

② **बकाया की बड़ी धनराशि**
↳ GeM से पूर्व की खरीदारी के बकाया को ही अभी पूरी तरह सुलझाया नहीं गया है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

⑤ जालसाजी व भ्रष्टाचार
↳ कई बार नकली व कम गुणवत्ता पूर्ण वस्तुएँ संस्थाओं को उपलब्ध कराई जाती हैं।

⑥ इरादा के क्षेत्रों तक पहुँच न होना
↳ कई क्षेत्रों तक आपूर्ति कठिन व विलम्बित होती है।

⑦ निर्णय लेने में विलम्ब
↳ कई प्रक्रियाओं के गुजरने के बाद किसी निर्णय पर सहमति होती है इससे समय बढ़ जाता है।

⑧ न्यूनतम लागत का पालन न होना
↳ सामान्यतः अधिक मूल्यों पर वस्तुओं का क्रय कर लिया जाता है।

⑨ प्रतिस्पर्धी का अभाव
↳ इससे न्यूनतम कीमत नहीं मिल पाती।

GeM द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुधार

- पारदर्शिता
  - पहले भ्रष्टाचार व कागजी कार्रवाईयों के कारण अनियमितताएं थी।
- न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप
  - भ्रष्टाचार को कम करने के साथ - निर्णय लेने व प्रक्रियाओं में पहले की अपेक्षा तीव्रता आई है
- रोजगार का सृजन
  - इसमें MSME व स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा दिया जाता है।
- बेहतर गुणवत्ता
  - विभिन्न विकल्पों के खुलने के कारण
- डिजीटलीकरण
  - पारदर्शिता के साथ न्यूनतम मूल्य को प्राप्त किया जा सकता है।

आवश्यकता है कि GeM में सुधार लाकर सरकारी खरीद प्रणाली को और अधिक कुशल बनाया जाए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. A reformed system of recruitment, training and evaluation needs to be put in place to take forward the development of a highly efficient and accountable civil service. Discuss in the context of India. **(250 words) 15**

अत्यधिक कुशल और जवाबदेह सिविल सेवा के विकास को आगे बढ़ाने के लिए भर्ती, प्रशिक्षण और मूल्यांकन की एक संशोधित प्रणाली लागू करने की आवश्यकता है। भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

सिविल सेवा को अधिक कुशल व जवाबदेह बनाने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं जैसे -

- बहुविकल्पीय फीडबैक
- बेहतर प्रशिक्षण
- ई ऑफिस
- ग्रेडर की जगह जोन के आधार पर ग्रेडर का आवंटन आदि।

किंतु इसके साथ ही भर्ती व प्रशिक्षण व मूल्यांकन में एक संशोधित प्रणाली की आवश्यकता है।

भर्ती

कमियाँ
- सामान्यज्ञ
- प्रबंधन का प्रशिक्षण नहीं होता
- अत्यधिक संख्या
- योग्यता व पद के मानको

का मिलान न होना।

संशोधित प्रणाली
- योग्यता व पद की आवश्यकताओं के मिलान के आधार पर पद का आवंटन
- स्थानांतरण व भर्ती की प्रक्रिया को अधिक कुशल व पक्ष बनाया जाए
- साक्षात्कार आदि को अधिक मानकीकृत करना।
- परीक्षा से प्राप्त प्रतिभा पूल का उपयोग राज्य स्तरीय सेवाओं में किया जा सकता है।
- विशेषज्ञता पर बल
- भर्ती की लेटरल प्रक्रिया में बाजार के समान वेतन व चयन प्रक्रिया में सुधार।

प्रशिक्षण

कमियाँ
- संवेदनशीलता का अभाव
- दीर्घकालिकता का अभाव
- बेहतर मूल्यांकन की आवश्यकता

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रशिक्षण की संशोधित प्रणाली
- अध्ययन के बजाय प्रयोगों पर और बल देना
- नैतिकता पर बल
- संधारणीयता पर बल ताकि एकेडमी से बाहर आने के बाद भी इसके मूल्यों को सहेज कर रखा जाए।

मूल्यांकन

कमियाँ
- 360° मूल्यांकन का बेहतरी से आज क्रियान्वयन न होना
- आवधिक मूल्यांकन का अभाव
- अपारदर्शिता

संशोधित प्रणाली
- बहुहितधारक मूल्यांकन
- पारदर्शिता
- प्रोत्साहन की नीति
- अनिवार्य सेवानिवृत्त करना
- आवधिक मूल्यांकन

भर्ती, प्रशिक्षण व मूल्यांकन में सुधार के माध्यम से मजबूत सिविल सेवा को और अधिक दक्ष व कुशल बनाया जा सकेगा।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. Despite initiatives taken by the Indian government to achieve critical goals in the education sector, major interventions are required to tackle learning poverty as well as the persisting inequalities. Discuss. **(250 words) 15**

शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई पहलों के बावजूद, लर्निंग पॉवर्टी (अधिगम निर्धनता) के साथ-साथ विद्यमान असमानताओं से निपटने के लिए बड़े हस्तक्षेपों की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

शिक्षा के क्षेत्र मे सरकार द्वारा विभिन्न पहले की गई है-

- शिक्षा का अधिकार अधि. 2009
→ समग्र शिक्षा अभियान
→ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
→ PM पोषण अभियान (मध्याह्न भोजन योजना)

आदि।

लर्निंग पावर्टी व विद्यमान असमानताएं

- लर्निंग आउटकम का कम होना

↳ कोरोना महामारी से पहले लगभग 52% 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे साधारण पाठ को पढ़ नही पाते थे, महामारी के बाद यह आंकड़ा 70% तक पहुँच गया है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

① अवसंरचना का अभाव
- पर्याप्त भवन, शौचालयों का अभाव
- स्वच्छता का अभाव
- प्रयोगशालाओं का अभाव
- व्यक्तिगत कम्प्यूटरों का अभाव

② अध्यापक के स्तर पर सुधारों का अभाव
- पर्याप्त उपस्थिति सुनिश्चित न होना
- अध्यापक प्रशिक्षण का अभाव
- संवेदीकरण का अभाव

③ असमानताएँ
- SC/ST वर्ग का अधिक स्कूल छोड़ने की दर होना
- महिलाओं के साथ शिक्षा में लैंगिक भेदभाव
- दिव्यांगों की शिक्षा पर कम बल

④ नवाचार/रचनात्मकता का अभाव

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आवश्यक हस्तक्षेप की आवश्यकता।

अवसंरचनात्मक विकास

- भवन, शौचालय, प्रयोगशाला, कार्यात्मक कम्प्यूटर आदि परक
- स्वच्छता, पेय जल व बिजली की पर्याप्त सुविधाएं
- महिलाओं के लिए मासिक धर्म व अन्य स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना

अध्यापक के स्तर पर

- पर्याप्त व कुशल प्रशिक्षण
- संवेदीकरण किया जाए।
- उपस्थिति सुनिश्चित करना।

समानता -

- SC/ST, महिला, दिव्यांगों के लिए सकारात्मक कार्रवाई करना।

नवीन मांगों के अनुसार ढालना

- विश्व की मांग के अनुसार नैतिक, पर्यावरणीय मुद्दों को पाठ्यक्रम में शामिल करना
- नवाचार पर बल।

उपर्युक्त के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से देश की विकास गति को गति दिया जा सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. In light of the burgeoning burden of both communicable and non-communicable diseases, there is a need to revamp the public health surveillance system in India. Discuss. **(250 words) 15**

संचारी और गैर-संचारी दोनों प्रकार के रोगों के बढ़ते बोझ के आलोक में, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

डिजीज बर्डन के संदर्भ में भारत एक सुभेद्य देश है। संचारी रोगो के साथ गैर संचारी रोगो की वृद्धि ने कई चुनौतियाँ उत्पन्न की है।

1990 मे गैर संचारी रोगो (NCDs) से होने वाली मौतें 37% से बढकर 2019 मे 65% तक पहुंच गई है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली में कमियाँ

- पर्याप्त डेटा का अभाव
  - इससे वास्तविक स्थिति का आकलन नही हो पाता
  - बेहतर लक्ष्यीकरण के साथ निर्णय नही ले पाते

(i) अवसंरचना का अभाव
↳ वहनीय सुविधाओं का अभाव
↳ माँग के अनुसार आपूर्ति में संतुलन न हो पाना

(ii) असमानताएँ
↳ आदिवासी क्षेत्रों तक पहुँच न होना
↳ महिलाओं SC/ST व अन्य कमजोर वर्गों की पहुँच का अभाव

(iii) बचाव से अधिक निदान पर बल
↳ इससे रोगों के संचारीकरण से पूर्व ही निपटान हो सकता है किंतु वर्तमान प्रणाली में यह कारक अधिक महत्वपूर्ण नहीं हुआ है।

(iv) निजी क्षेत्र का पूरक न बन पाना
↳ वहनीयता की समस्या
↳ अनैतिक प्रैक्टिस को अपनाया जाना। eg- सर्जरी व अत्यधिक दवाओं के लिखने पर बल

(v) समुदाय आधारित दृष्टिकोण का अभाव

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली में निम्न सुधारों की आवश्यकता है-

① अवसंरचना का निर्माण
↳ ताकि सभी कमजोर वर्गों का आउट ऑफ पॉकेट व्यय कम किया जा सके।

② डेटा एकत्रण पर बल
↳ इसके साथ ही डेटा विश्लेषण में संचार तकनीकी का प्रयोग किया जाना चाहिए।

③ बचाव पर बल
↳ जन-जागरूकता बढ़ाना
↳ लोग जीवन की अच्छी आदतों पर बल देना।
↳ परम्परागत चिकित्सा पद्धति जैसे योग का प्रसार
↳ शारीरिक व्यायाम पर बल देना
↳ जंक फूड के प्रति जागरूकता फैलाना।

④ लक्ष्यीकरण पर बल
उपर्युक्त के माध्यम से भारत में बेहतर मानव संसाधन निर्मित किए जा सकते हैं।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. The repercussions of the ongoing economic crisis in Sri Lanka extend beyond its borders. Discuss with specific reference to India. Also, mention the steps that India has taken to assist Sri Lanka tide over the crisis.

(250 words) 15

श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट का प्रभाव उसकी सीमाओं से परे भी पड़ रहा है। भारत के विशिष्ट संदर्भ में विवेचना कीजिए। साथ ही, उन कदमों का भी उल्लेख कीजिए जो भारत ने इस संकट से निपटने में श्रीलंका की सहायता के लिए उठाए हैं।

श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकटो में से एक से जूझ रहा है।

- मुद्रास्फीति
- फॉरेक्स रिजर्व खाली होना
- राजनीतिक अस्थिरता
- ऋण-GDP अनुपात 2021 तक करीब लगभग 106% तक पहुंच गया है।

श्रीलंका के संकट का भारत पर प्रभाव

- **प्रवासी समस्या**
  - भारत में 5000 से भी अधिक प्रवासी प्रवेश कर चुके हैं। इन्हे शरण देना, आवश्यकताओं की पूर्ति करना, संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ डालता है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

↳ देश की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती पहुँच सकती है।

② चीन की श्रीलंका में बढ़ती सामरिक भूमिका

↳ यह भारत के हितों के अनुरूप नहीं है।

↳ पड़ोसी देश में चीन के हस्तक्षेप से भारत को लिए सुरक्षा खतरे उत्पन्न हो सकते हैं।

↳ श्रीलंका हिन्द महासागर का महत्वपूर्ण देश है। अतः सेचार मार्ग (sea lanes) व चोक प्वाइंट्स की दृष्टि से यह घातक सिद्ध हो सकता है।

③ व्यापार प्रभावित

↳ श्रीलंका में भारत द्वारा निर्यात किया जाता है।

↳ भारतीय कंपनियां श्रीलंका में निवेश से संबद्ध हैं।

④ राजनीतिक अस्थिरता

↳ आंतरिक स्थिति से

उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता का भारत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

- तमिल मुद्दा फिर से उठ खड़ा हो सकता है।

इनसे निपटने के लिए भारत द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता

- भारत ने लगभग $ 3.8 billion की मदद की है।
- $400 million का करेंसी स्वैप किया है।
- $500 million के ऋण के भुगतान को स्थगित कर दिया है।
- महत्वपूर्ण आवश्यकता की वस्तुएँ जैसे - गेहूँ, चावल, चीनी आदि उपलब्ध कराई गई है।

पड़ोसी देशों में शांति व स्थिरता भारत के हित में है अतः इन्हे स्थापित करने के लिए भारत को यथासंभव श्रीलंका की मदद करनी चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. India is a reliable partner in the Indian Ocean Region and can take on the role of being the net security provider in the region. Discuss.

(250 words) 15

भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एक विश्वसनीय भागीदार है और इस क्षेत्र में निवल सुरक्षा प्रदाता होने की भूमिका निभा सकता है। विवेचना कीजिए।

निवल सुरक्षा प्रदाता से तात्पर्य है देश द्वारा अपनी सुरक्षा व्यवस्था से भी आगे जाकर क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था को संचालित व दिशा देने का कार्य किया जाना।

निवल सुरक्षा प्रदाता के रूप में देश द्वारा 4 बिंदुओं पर बल दिया जाता है

- अन्य देशों का क्षमता निर्माण
- सहयोग
- प्रशिक्षण
- सुरक्षा उपलब्ध कराना

भारत हिंद महासागर में विश्वसनीय भागीदार है

① भारत की अति सक्रिय भूमिका
- इस क्षेत्र में किसी

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भी आपदा के दौरान भारत द्वारा सर्वप्रथम अभिक्रिया की जाती है उदा.- मालदीव मे जल संकट को दूर करने के लिए सहायता भेजना।

- भारत की शांतिपूर्ण व अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर बल देने की प्राथमिकता
  - ↳ इससे इस क्षेत्र के देशों मे भारत के प्रति विश्वास बना है।
  - ↳ भारत द्वारा इस क्षेत्र के देशों की सम्प्रभुता की रक्षा की जाती है।
- सांस्कृतिक संबंध व समन्वय व सॉफ्ट पावर
  - ↳ भारत इन सभी देशों के साथ बेहतर सॉफ्ट पावर रखता है।
  - ↳ बेहतर, कुशल व अच्छे संबंधों का निर्माण

ये भारत को निवल सुरक्षा प्रदाता के रूप में भूमिका निभाने मे मदद कर सकते है

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारत की निवल सुरक्षा प्रदाता के रूप मे भूमिका

विश्वसनीय भागीदार
- जैसा पूर्व की चर्चा से ज्ञात होता है कि भारत का इन देशों के साथ विश्वसनीय संबंध है।

भारत की SAGAR रणनीति, पड़ोसी देश पहले
- SAGAR- सिक्योरिटी एण्ड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन
- आर्थिक व सांस्कृतिक संबंध

भारत द्वारा इस क्षेत्र मे सैन्याभ्यास किया जाए
- ये इन्टरऑपरेबिलिटी को बढाते हैं

क्षमता निर्माण
- छोटे देशों की सेना को प्रशिक्षण देना।

इसके साथ निवल सुरक्षा प्रदाता के रूप मे भारत को और मजबूत सैन्य ढाचे व सैन्य व्यवस्थाओं के अत्याधुनिकीकरण की आवश्यकता है।